

# तीर निशाने पर विशिखा

मूल्य: 25 रुपये

वर्ष: 06 अंक: 10 अक्टूबर 2024 पृष्ठ: 32

राजस्थान संस्करण



**तिरुपति प्रसाद विवाद**

**घी की कीमतों से शक होने पर चर्बी का हुआ खुलासा**

# विशिखा न्यूज़ 24x7



आपकी बात, आपके साथ



## राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

# विशिखा

अब डिजिटल एडिशन में भी उपलब्ध



[www.vishikhamedia.in](http://www.vishikhamedia.in)



# अंदर

## तिरुपति प्रसाद विवाद

### घी की कीमतों से शक होने पर चर्बी का हुआ खुलासा



मिलावटी घी पाए जाने के बाद आंध्र प्रदेश में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेडी इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं, वहीं वर्तमान सरकार उन पर गंभीर आरोप लगा रही है।

06

10

23 साल पूर्व जब राजनाथ सरकार के ऐसे ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी रोक



18

न्यायपालिका को अपराधी नहीं, पीड़ित के पच में खड़ा होना चाहिए

20

अब 3D मोटावर्स पर दिखेंगे लखनऊ-प्रयागराज के पर्यटन स्थल

24

95 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले तातकिस्तान में हिजाब पर रोक



12

बंगाल का नया कानून अपराजिता बिल: पश्चिम बंगाल में अब दुष्कर्मी को मिलेगी फांसी

14

शास्त्री जी की मौत पर जब झुक गए थे भारत, पाक और रूस के झंडे



20

राजस्थान का भूतिया किला, जहाँ शाम होते ही पसर जाता है सन्नाटा



मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रियल श्रीवास्तव

सम्पादक

अनिल कुमार श्रीवास्तव

डिजाइन

देवेन्द्र नेगी, उत्तराखण्ड

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं  
संपादक अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा  
भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, डी.बी. कॉर्प  
लिमिटेड शिवदासपुरा, टॉक रोड, जयपुर  
से छपावाकर एवं विशिखा मीडिया  
191/56 (जानकी देवी स्कूल के पास)  
सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर,  
जयपुर- 302033  
राजस्थान के लिए प्रकाशित

पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में प्रकाशित  
सामग्री के विषय में अपनी प्रतिक्रियाएं एवं  
सुझाव अवश्य भेजें। अपनी प्रतिक्रियाएं एवं  
सुझावों को आप हमें  
vishikhamedia@gmail.com पर ई-मेल भी  
कर सकते हैं।

लेखकों से निवेदन है कि कृपया अपनी  
स्व-लिखित एवं मौलिक रचनाएँ ही भेजें।  
रचनाओं के साथ अपना पूरा नाम, पता,  
मोबाइल नंबर, ई-मेल एवं फोटो अवश्य भेजें।  
रचनाओं के छापने या न छापने का अधिकार  
संपादकीय मंडल का होगा। अस्वीकृत रचनाएँ  
लौटाई नहीं जाएंगी।  
पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख एवं रचनाओं में  
संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है।  
पत्रिका में प्रकाशित आलेख एवं रचनाएँ लेखकों  
के निजी विचार हैं। प्रकाशित सामग्री के उपयोग  
करने से पूर्व में संपादक की लिखित सहमति  
आवश्यक है।

\*किसी भी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर  
(राजस्थान) होगा।

\*पत्रिका में प्रकाशित कुछ चित्र, लेख एवं आंकड़ों  
को इन्टरनेट एवं अन्य वेबसाइट से लिया गया है।



# सम्पादक की कलम से



अनिल कुमार श्रीवास्तव

निर्भया केस के बाद देश को झकझोर देने वाले कोलकाता के आर जी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसकी निर्मम तरीके से की गई हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश में एक बेटी के साथ हुई निर्ममता से कोलकाता सहित पूरे देश में धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। कोलकाता में साथी डॉक्टरों ने काम का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले तो कोलकाता में साथी डॉक्टरों के साथ बात करना जरूरी नहीं समझा, पर डॉक्टरों के विरोध के चलते ममता बनर्जी ने उनसे मिली और उनकी मांगों को मानकर उनसे हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया, और उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया। फिलहाल आर जी कर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष की गिरफ्तारी तथा कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को हटाने की कार्यवाही तो हो गई, पर इसके साथ ही अन्य मांगों को मानने के आश्वासन मिलने के साथ ही फिलहाल वहां के कुछ डॉक्टर अभी तो कम पर आ गए, लेकिन उनके दिलों में जल रही आग की चिंगारी अभी भी बाकी है...

शेष फिर...

अनिल

# ‘मन की बात’ के 10 साल पूरे होने पर मोदी हुए भावुक, कहा- श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं

पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को हौसला देने वाली कहानियां बहुत पसंद आती हैं। अक्सर यह धारणा होती है कि जब तक कोई चटपटी या नकारात्मक बात न हो, उसे खास तवज्जो नहीं मिलती।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 114वीं बार श्मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आज का एपिसोड मेरे लिए बेहद भावुक करने वाला है, क्योंकि ‘मन की बात’ की यह यात्रा अब 10 साल पूरे कर रही है। उन्होंने बताया कि ‘मन की बात’ की शुरुआत 10 साल पहले 3 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन हुई थी। यह एक पवित्र संयोग है कि इस साल जब 3 अक्टूबर को इस यात्रा के दस साल पूरे होंगे, तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। इस लंबी यात्रा के कई ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। करोड़ों श्रोता इस यात्रा के साक्षी और सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने मुझे देश के हर कोने से महत्वपूर्ण जानकारी दी। श्रोता ही इस कार्यक्रम की असली धुरी हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को हौसला देने वाली कहानियां बहुत पसंद आती हैं। अक्सर यह धारणा होती है कि जब तक कोई चटपटी या नकारात्मक बात न हो, उसे खास तवज्जो नहीं मिलती। लेकिन ‘मन की बात’ ने यह साबित किया है कि देशवासियों के बीच सकारात्मक सूचनाओं की कितनी मांग है। प्रेरणादायक कहानियां और हौसला बढ़ाने वाली घटनाएं लोगों को बेहद पसंद आती हैं।

उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक पक्षी होता है श्चकोरश, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सिर्फ बारिश की बूंद ही पीता है।

‘मन की बात’ में हमने देखा है कि लोग भी चकोर की तरह देश की उपलब्धियों और सामूहिक प्रयासों को गर्व से सुनते हैं। ‘मन की बात’ की दस साल की यात्रा एक ऐसी माला की तरह है, जिसमें हर एपिसोड के साथ नई कहानियां, नए कीर्तिमान और नए व्यक्तित्व जुड़ते जाते हैं। हमारे समाज में जो भी सामूहिकता के साथ कार्य हो रहे हैं, उन्हें श्मन की बात के माध्यम से सम्मान मिलता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं ‘मन की बात’ के लिए आई चिट्ठियों को पढ़ता हूँ तो मेरा मन गर्व और ऊर्जा से भर जाता है। हमारे देश में कितने प्रतिभाशाली लोग हैं, जो निस्वार्थ भाव से समाज और देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। उनके बारे में जानकर मुझे अपार ऊर्जा मिलती है। श्मन की बात की पूरी प्रक्रिया मेरे लिए ऐसी है जैसे मंदिर जाकर ईश्वर के दर्शन करना। ‘मन की बात’ की हर घटना, हर बात, और हर चिट्ठी मुझे जनता जनार्दन के दर्शन कराने जैसी लगती है, जो मेरे लिए ईश्वर के समान हैं।



## तिरुपति प्रसाद विवाद

# घी की कीमतों से शक होने पर चर्बी का हुआ खुलासा

मिलावटी घी पाए जाने के बाद आंध्र प्रदेश में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं, वहीं वर्तमान सरकार उन पर गंभीर आरोप लगा रही है।



तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी पाए जाने के बाद आंध्र प्रदेश में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं, वहीं वर्तमान सरकार उन पर गंभीर आरोप लगा रही है। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं में घी की जगह कथित तौर पर मछली के तेल और जानवरों की चर्बी के उपयोग का मामला सामने आने के बाद विवाद गहरा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में मिलावट का दावा किया था, जिसके बाद पूरे देश में श्रद्धालुओं ने चिंता व्यक्त की। न केवल केंद्र सरकार बल्कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले पर अपनी चिंता जाहिर की है।

तिरुपति लड्डुओं में चर्बी का विवाद तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दो दिन पहले एक लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि मंदिर के प्रसाद में उपयोग किए जाने वाले घी में जानवरों की चर्बी मिली हुई है। उन्होंने कहा कि यह मिलावट पिछली सरकार के दौरान दिए गए घी के ठेके के कारण हुई है। नायडू ने इस मामले में भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को न बख्ताने की बात कही। मंदिर समिति तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अधिकारी श्यामला राव ने भी स्वीकार किया कि मंदिर की पवित्रता भंग हुई है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने टीटीडी के

कार्यकारी अधिकारी का पद संभाला, तो मुख्यमंत्री नायडू ने घी और लड्डुओं की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की थी। टीटीडी के अनुसार, हर महीने लगभग 42,000 किलो घी लड्डुओं के लिए खरीदा जाता है, लेकिन घी की गुणवत्ता की जांच के लिए कोई आंतरिक या बाहरी प्रयोगशाला नहीं थी। घी की कीमत भी संदिग्ध थी, क्योंकि शुद्ध घी की कीमत 500 रुपये प्रति किलो होनी चाहिए थी, लेकिन इसे 320 रुपये में खरीदा गया।

मामला तब सामने आया जब सत्ता परिवर्तन के बाद चंद्रबाबू नायडू ने लड्डुओं में मिलावट की आशंका जाहिर की और गुजरात स्थित डेयरी विकास बोर्ड की लैब में घी के नमूनों की जांच कराई। रिपोर्ट में सोयाबीन, मछली का तेल, बीफ टैलो और अन्य तत्व पाए गए। यह घी चेन्नई की एक कंपनी द्वारा सप्लाई किया गया था, जिसे अब बैन कर दिया गया है।

इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए टीटीडी ने कहा कि अब प्रसाद पूरी तरह से पवित्र और बेदाग है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगी है और कांग्रेस नेता वार्डेंस शर्मिला ने सीबीआई जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने भी प्रसाद में मिलावट को लेकर चिंता जताई है, जबकि जगन मोहन ने आरोपों को निराधार बताया है। मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है, जहां इसकी जांच की मांग की गई है।

# तिरुपति मंदिर को चढ़ावे में मिला 11329 किलो सोना, 1167 करोड़ की आय सिर्फ ब्याज से

तिरुपति बालाजी, जिसे तिरुमला मंदिर भी कहा जाता है, भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। यहां हर साल अरबों रुपये का चढ़ावा आता है।

आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। तिरुपति बालाजी, जिसे तिरुमला मंदिर भी कहा जाता है, भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। यहां हर साल अरबों रुपये का चढ़ावा आता है। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास और इसे सबसे धनी मंदिरों में क्यों गिना जाता है। साथ ही, यहां हर साल कितनी संपत्ति आती है? तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर का वर्तमान बजट 5000 करोड़ रुपये से अधिक है, इसे संचालित करने वाला टीटीडी ट्रस्ट की कुल संपत्ति 18,000 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। टीटीडी का कुल स्वर्ण भंडार 11,329 किलोग्राम है।

## तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास:

तिरुपति जिले के तिरुमला पहाड़ियों में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप को समर्पित है और इसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन है।

## मंदिर की संपत्ति

तिरुपति बालाजी मंदिर का बजट 5000 करोड़ रुपये से भी अधिक है, और भगवान बालाजी की संपत्ति देश की कई बड़ी कंपनियों से भी अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मंदिर ने 1,161 करोड़ की जमा राशि अर्जित की। इस राशि से टीटीडी

के सावधि जमा 18,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गए। इसके साथ ही, मंदिर ने 1,031 किलोग्राम सोने का संग्रह किया, जिससे इसका कुल स्वर्ण भंडार 11,329 किलोग्राम हो गया। टीटीडी ने 2024-25 के लिए 5,142 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया, जो 2023-24 के बजट 5,123 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है।

## आय के स्रोत

श्री वेंकटेश्वर मंदिर को कई स्रोतों से आय प्राप्त होती है, जिसमें सबसे बड़ा स्रोत भक्तों द्वारा दिया गया चढ़ावा है, जिसे श्रुंजी कनुकाश कहा जाता है। भक्तों ने एक साल में 1,611 करोड़ रुपये का चढ़ावा दिया। इसके अलावा, 1,167 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में आए, और प्रसादम से 600 करोड़ रुपये की कमाई हुई। अन्य स्रोतों में दर्शन से 338 करोड़ रुपये, और कल्याण मंडपम व अन्य सेवाओं से 246 करोड़ रुपये शामिल हैं।

## भक्तों का योगदान

भक्तों ने भगवान बालाजी के नाम पर 11,225 किलोग्राम सोना दान किया है। इसके अलावा, टीटीडी के पास 6,000 एकड़ वन भूमि और 7,636 एकड़ अन्य अचल संपत्तियां हैं। मंदिर के पास देशभर में 71 मंदिर भी हैं, और 535 अन्य संपत्तियां हैं जिनसे सालाना 4 करोड़ रुपये की आय होती है।

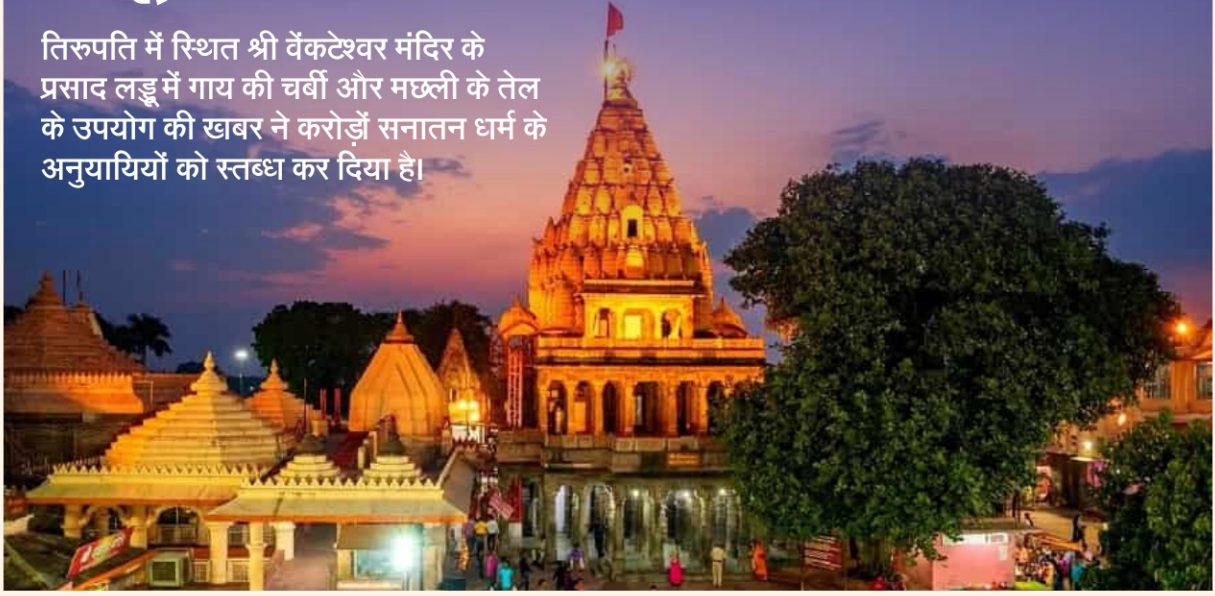
## मंदिर के बजट का उपयोग

2024-25 के बजट के अनुसार, टीटीडी ने कर्मचारियों के वेतन पर 1,733 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि सामग्री की खरीद पर 751 करोड़ रुपये खर्च हुए। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपये और इंजीनियरिंग रखरखाव के लिए 190 करोड़ रुपये का अनुमान है।



# जानिए कैसे बनते हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू और कहां से आता है इसके लिए घी-बेसन

तिरुपति में स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद लड्डू में गाय की चर्बी और मछली के तेल के उपयोग की खबर ने करोड़ों सनातन धर्म के अनुयायियों को स्तब्ध कर दिया है।



देश के सबसे लोकप्रिय और समृद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति में स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद लड्डू में गाय की चर्बी और मछली के तेल के उपयोग की खबर ने करोड़ों सनातन धर्म के अनुयायियों को स्तब्ध कर दिया है। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा इस जानकारी के सार्वजनिक होते ही मामला बढ़ गया और अब यह अदालत तक पहुंच चुका है, जहां जांच की मांग की जा रही है। यह मामला किस दिशा में जाएगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने देश के कई अन्य धार्मिक स्थलों के प्रसाद की शुद्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी संदर्भ में हम मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रसाद के बारे में जानेंगे। यह कैसे तैयार होता है, इसमें किस प्रकार का घी उपयोग होता है और इसकी शुद्धता की क्या व्यवस्था है।



## नो प्रॉफिट और नो लॉस

तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर की

तरह, उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी भगवान महाकाल को लड्डू का भोग अर्पित किया जाता है। भक्तों को यह लड्डू प्रसाद सशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन

इसे नो प्रॉफिट—नो लॉस के आधार पर दिया जाता है। यानी लड्डू बनाने में जितना खर्च होता है, उसी के हिसाब से भक्तों से शुल्क लिया जाता है। मंदिर समिति इस पर कोई लाभ नहीं कमाती।

भक्तों को यह लड्डू 50 रुपये से लेकर 400 रुपये तक के पैकेट में मिलता है।

### दाल पीसकर बनता है बेसन, शुद्ध घी का उपयोग

श्री महाकालेश्वर मंदिर का प्रसाद चिंतामण क्षेत्र स्थित मंदिर समिति की इकाई में तैयार होता है। इसकी पूरी प्रक्रिया अधिकारियों की देखरेख में की जाती है। मंदिर प्रबंध समिति बेसन की बजाय चने की दाल खरीदती है, जिसे मंदिर में लगी चक्की में पीसकर बेसन बनाया जाता है। लड्डू में उपयोग होने वाला देसी घी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत सांची डेयरी से खरीदा जाता है, और सभी सामग्री की गुणवत्ता की जांच के बाद ही उपयोग की जाती है।

### टेस्टिंग के बाद ही मिलते हैं ड्रायफ्रूट्स

श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति को प्रसाद की शुद्धता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें '।ळ्म भोग प्रसाद और 5-स्टार रेटिंग शामिल हैं। लड्डू में उपयोग होने वाले ड्रायफ्रूट्स भी टेस्टिंग के बाद ही शामिल किए जाते हैं। अब तक कोई भी लड्डू का सैंपल फेल नहीं हुआ है, और प्रसाद की



उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है।

### हर दिन 30 क्विंटल लड्डू बनाए जाते हैं

लड्डू यूनिट के प्रभारी कमलेश सिसोदिया के अनुसार, सामान्य दिनों में 25 से 30 क्विंटल लड्डू बनाए जाते हैं, और विशेष अवसरों जैसे सावन सोमवार को 50-65 क्विंटल लड्डू तैयार किए जाते हैं। लड्डू के पैकेट 50, 100, 200 और 400 रुपये में उपलब्ध होते हैं।

### अयोध्या में भेजे गए थे महाकाल के लड्डू

श्री महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसाद को उसकी शुद्धता के कारण अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दौरान भेजा गया था। यह लड्डू 20 दिनों तक खराब नहीं होते, जिससे श्रद्धालु इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं।

### प्रसाद की गुणवत्ता पर अवॉर्ड

श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष शर्मा ने बताया कि मंदिर को लड्डू प्रसाद की उच्च गुणवत्ता के लिए तीन से चार बार पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा दिया गया सम्मान भी शामिल है। तिरुपति और महाकाल दोनों स्थानों पर भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है, लेकिन तिरुपति के लड्डू में नुक्ति और कपूर डाला जाता है, जबकि महाकाल का प्रसाद बेसन का होता है, जो जल्दी खराब नहीं होता।

### जांच की आवश्यकता

महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा के अनुसार, तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद की गड़बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे मामलों में कड़ी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए।



# 23 साल पूर्व जब राजनाथ सरकार के ऐसे ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी रोक

सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ ने बीते गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। पीठ के छह जजों के कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब-कैटेगरी को भी आरक्षण दिया जा सकता है।



## अजय कुमार, लखनऊ

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बैंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अनुसूचित जातियों में अति पिछड़ी अनुसूचित जातियों को चिन्हित करके उन्हें फायदा पहुंचाने के लिये कोटा में कोटा का जो आदेश पारित किया है। वह हिन्दुस्तान में लम्बे समय से चल रही आरक्षण की सियासत में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अभी इस पर बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के बड़े नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, फिलहाल सिर्फ बीजेपी ही अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गद्गद है और उसके शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान द्वारा इसे सत्य की जीत बताया गया है। सबसे खास बात यह है कि पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण में जैसे क्रिमी लेयर को बाहर रखा जाता था, वैसे ही अब एससी/एसटी को मिलने वाले आरक्षण में भी क्रिमी लेयर लागू होगी।

बहरहाल, यूपी में ऐसा ही प्रयास 23 साल पूर्व 2001 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया था, जिस पर राजनाथ सिंह सरकार में ही राज्य मंत्री



और शिकोहाबाद से विधायक अशोक यादव अपनी ही सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गये थे और तब सुप्रीम कोर्ट ने उनके (राजनाथ सरकार) फैसले पर रोक लगा दी थी जिसे अब उसने कानून बना दिया है। अब राजनाथ सिंह मौजूदा केंद्र सरकार में गृहमंत्री हैं। राजनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के समूहों को उप समूहों बांटकर तय आरक्षित कोटे में विभाजन का प्रयास किया था। राजनाथ सरकार ने जो समूह बनाए थे वे आय आधारित क्रिमी लेयर या नॉन क्रिमी लेयर जैसे नहीं थे, बल्कि कई जातियों को आरक्षण के दायरे से ही बाहर करने का प्रयास किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजनाथ सरकार की कोशिशों पर पानी फेर दिया था, और उनके प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया।

उस समय उत्तर प्रदेश की राजनाथ सिंह सरकार ने पिछड़ी जातियों के 27 फीसदी कोटे में यादव, अहिर और यदुवंशियों का कोटा 5 फीसदी तय किया था, जबकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के 21 फीसदी कोटे में जाटव, चमार और धुसिया जातियों का कोटा 10 फीसदी तय किया गया था। अनुसूचित जनजातियों का कोटा घटा कर दो से एक फीसदी कर दिया गया था, ताकि प्रदेश में कुल कोटा 50 फीसदी तक ही बना रहे। राजनाथ सरकार के फैसले का राजनीतिक दलों समेत जाति समूहों ने भी कड़ा विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर चुका है, हालांकि राजनाथ सिंह की निजी वेबसाइट पर ये एक उपलब्धि के रूप में दर्ज है। बता दें जून, 2001 में राजनाथ सिंह एक समिति बनाई थी, जिसे उन्होंने 'सामाजिक न्याय समिति'

नाम दिया था। यूपी सरकार के तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, स्वास्थ्य मंत्री रमापति शास्त्री और विधान परिषद सदस्य दयाराम पाल सदस्य थे। समिति को ये पता करने जिम्मेदारी दी गई थी कि आरक्षण का लाभ उन्हें मिल पा रहा है या नहीं, जिन्हें इनकी आवश्यकता है। समिति को आरक्षण नीति में बदलाव की सिफारिशें देने का निर्देश भी दिया गया था। भाजपा सरकार ने ये फैसला 'आरक्षण नीतियों की गड़बड़ियाँ' दूर करने के लिए किया था।

सामाजिक न्याय समिति ने 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। भाजपा सरकार ने उसके बाद एक सामाजिक न्याय (30 जुलाई से 6 अगस्त, 2001) सप्ताह मनाया, जिसमें समिति के सुझावों पर राय मांगी गई थी। राजनाथ सरकार ने उस समय सरकार नौकरियों में जातियों के कुल प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण भी कराया था। उस सर्वे के बाद राजनाथ सरकार ने ये नतीजा निकाला था कि आरक्षण अधिकांश लाभ पिछड़ी जातियों में यादवों को और अनुसूचित जातियों में जाटव, चमार और धुसिया को ही मिल रहा है। इन्हीं नतीजों के बाद यादवों और जाटवों को आरक्षण सीमित कर दिया गया था। दरअसल, हाल में आरक्षण में कोटे में कोटा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस समय आया जब सात जजों की संविधान पीठ ईवी चिन्नेया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 2004 के उसके फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है या नहीं, पर विचार कर रहा थी, जिसमें माना गया था कि अनुसूचित जातियों के बीच किसी तरह का उप-विभाजन नहीं हो सकता। ताजा फैसला उन राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा जो प्रमुख अनुसूचित जातियों की तुलना में आरक्षण के बावजूद को आरक्षण का व्यापक लाभ देना चाहते हैं।

कोर्ट के इस तथ्य पर मुहर लगाने के बाद कि ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य यही बताते हैं कि अनुसूचित जातियाँ एक समरूप वर्ग नहीं हो सकतीं, राज्यों को आरक्षण पर अपने हिसाब से

कानून बनाने का मौका मिल सकेगा। उप-वर्गीकरण रणनीति का पंजाब में वाल्मीकि और महजबी सिखों, आंध्र प्रदेश में मडिगा के अलावा बिहार में पासवान, यूपी में जाटव और तमिलनाडु में अरुंधतिर समुदाय पर सीधा असर पड़ेगा। इस मामले में शीर्ष कोर्ट की पीठ ने 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उस समय अदालत ने कहा कि उप-वर्गीकरण की अनुमति न देने से ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, जिसमें इस वर्ग के सम्पन्न लोग ही सारे लाभ हड़प लेंगे।

बता दें इससे पहले, 2004 में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया था कि यह अधिसूचित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत किस समुदाय को आरक्षण का लाभ मिल सकता है। राज्यों को इसमें किसी भी तरह के संशोधन का अधिकार नहीं है। तब पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से वर्ष 2000 में लाए गए इसी तरह के एक कानून को रद्द कर दिया। ई. वी. चिन्नेया मामले में शीर्ष कोर्ट ने आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम, 2000 को समानता के अधिकार का उल्लंघन करार देते हुए रद्द कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधान सम्मत बताया वहीं चार न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई जैसी ओबीसी आरक्षण में है सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधानसम्मत बताया वहीं चार न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू बात अभी आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कि जाये तो सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधान सम्मत बताया, वहीं चार न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में

उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई, जैसी ओबीसी आरक्षण में है। सच यह है कि ओबीसी समाज की तरह एससी-एसटी समुदाय में भी कई जातियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति न केवल कहीं कमजोर है, बल्कि उन्हें अपने ही वर्ग की अन्य जातियों से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यह भी एक तथ्य है कि एससी-एसटी समुदाय में कई जातियाँ ऐसी हैं, जिन्हें आरक्षण का न के बराबर लाभ मिला है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियाँ उठाती हैं। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है।

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार का दुरुपयोग होने की भी आशंका जताई है, क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल वोट बैंक बनाने के लालच में एससी-एसटी जातियों का मनमाना उपवर्गीकरण कर सकते हैं।

ऐसे में यह जरूरी है कि राजनीतिक दलों यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है, न कि वोट बैंक की राजनीति का हथियार। एससी-एसटी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण में बंटवारा किया जाना इसलिए समय की मांग है, क्योंकि आइएएस-आइपीएस अधिकारियों के बच्चों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी स्थिति गांव में रहने वाले भूमिहीन-निर्धन लोगों के बच्चों जैसी है। अच्छा होगा कि एससी-एसटी आरक्षण का उप-वर्गीकरण करने के साथ ही उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाए। आरक्षित वर्गों में जो भी अपेक्षाकृत सक्षम और संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ तो है ही, वंचित-निर्धन लोगों के साथ किया जाने वाला अन्याय भी है। आरक्षण प्रदान करते समय यह देखा ही जाना चाहिए कि उसका लाभ पाने वाला पात्र

# बंगाल का नया कानून

## अपराजिता बिल: पश्चिम बंगाल में अब दुष्कर्मी को मिलेगी फांसी



पश्चिम बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मति से दुष्कर्म रोधी विधेयक पारित किया। इस विधेयक में पीड़िता की मौत या "कोमा" जैसी स्थिति में जाने पर दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे की मांग की, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून नहीं बनाए हैं।

इस विधेयक का नाम है "अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024"। इसका उद्देश्य दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधान लागू करना और महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है।

यह विधेयक कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को एक महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बाद देशव्यापी नाराजगी के संदर्भ में लाया गया है। डॉक्टर्स न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था।

विधेयक का उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और पॉक्सो अधिनियम 2012 में संशोधन करना है, ताकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामलों की त्वरित सुनवाई और कठोर सजा



सुनिश्चित की जा सके।

इसमें कई संशोधन प्रस्तावित हैं, जैसे दुष्कर्म के दोषियों के लिए कम से कम 10 साल की सजा और सामूहिक दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान। विधेयक में यौन हिंसा की शिकार महिलाओं की पहचान सार्वजनिक करने पर भी सजा को बढ़ाया गया है। हालांकि, विधेयक को लागू करने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होगी। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इसे राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। मुख्यमंत्री ने केंद्र से कानूनों में संशोधन करने की मांग की थी, लेकिन जब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो यह कदम उठाया गया।

# मुख्यमंत्री धामी ने राजस्थान के माउंट आबू स्थित आयोजित ग्लोबल समिट 2024 में प्रतिभाग किया

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'ग्लोबल समिट2024' में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने वैश्विक सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्वान जनों का स्वागत और अभिनंदन किया।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, जहां कणकण में शंकर का वास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य एक ओर जहां प्राकृतिक रूप से सुरम्य है वहीं आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट भी है। विश्व के कोनेकोने से लोग देवभूमि उत्तराखंड में आकर स्वयं की खोज करते हैं। स्वयं को साधना में लगाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग उन्हें पूछते हैं कि देवभूमि में कितने देवस्थान हैं या कितने प्रसिद्ध स्थान हैं तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि देवभूमि में जिधर भी आपकी नजर जाएगी वो हर स्थान देवों का है। हर स्थान हमारा हिम ग्लेशियर, नदियों से आच्छादित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी देवभूमि से आकर आप सबके बीच आकर आप सबके कार्यक्रम से जुड़ना, आप सबके बीच आने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे स्थान पर वही आ पाता है जिन पर बाबा की कृपा होगी। इसीलिए सब लोग यहां पर पहुँचे हैं।

उन्होंने कहा कि आज मैं भी एक जिज्ञासु बनकर आया हूँ, मुझे अपने भीतर भी एक आत्मिक शांति का एहसास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कई वर्षों से प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज के कार्यक्रमों में आते रहे हैं। बहुत बार संस्थान के लोग माउंट आबू आने के लिए कहते थे। मन में आने की बहुत इच्छा भी रही। इसके पीछे का कारण परमपिता परमात्मा का असीम आशीर्वाद भी है और इस स्थान की महत्ता भी है और राज योगिनी दीदी मां रतन मोहिनी से जो स्नेह यहां मिलता



है वह भी इसका बड़ा कारण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबके लिए यह गर्व का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ ही परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त भारत की भूमि से उपजा हुआ यह स्थान विश्व के कोनेकोने में आज शांति, सद्भाव और मानवता का संदेश देने का कार्य कर रहा है। सच में लोगों को स्वयं को खोजने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है। मैं आज यहां स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में आध्यात्मिक की महत्वपूर्ण भूमिका को ही समझने के लिए ही आया हूँ कि कैसे इन मूल्यों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं ताकि सभी के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम भारतीय जीवन दर्शन का सार है। परस्पर भाईचारे का संदेश आज भी प्रासंगिक है। जिस प्रकार से नई तकनीक हमें भौतिक सुख प्रदान करती है वैसे ही आध्यात्मिकता हमें आंतरिक सुख प्रदान करती है। हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य पूर्ण संतुलन बनाने का काम करती है। पूरे विश्व के अंदर यह संस्था करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम कर रहा है। ब्रह्माकुमारीज संस्था से जुड़ी बहने और भाइयों द्वारा जीवन जीने की कल

बहुत ही सरल शब्दों में लोगों को समझाया जाता है, उससे आमजनमानस में भी आसानी से इन विषयों को जानकर लोग अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। इस प्रकार के जो बदलाव हैं, इनको मैंने अपने जीवन में महसूस किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम आध्यात्मिकता को अस्तित्व के एक भागीदार के रूप में देखने लगते हैं तो हमारा मन स्वतः ही स्वच्छ होने लगता है। हमें अहसास होता है कि यह हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं है बल्कि जीवन की अनिवार्यता है। आध्यात्मिकता की वह शक्ति है जो शरीर को बाहरी व अंदरूनी रूप से स्वच्छ रखने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक दबावों को सहने के सामर्थ्य प्रदान करती है। स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण केवल आधुनिक तरीके व कानूनों से भी संभव नहीं है कि केवल हम कानून व अन्य तरह से इसको कर पाएं बल्कि इस लक्ष्य को जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करके ही हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर भारत सरकार के रेल एवं फूड प्रोसेसिंग मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट, गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन आदि उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

# शास्त्री जी की मौत पर जब झुक गए थे भारत, पाक और रूस के झंडे

**देश के दूसरे प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को होती है। उनके नेतृत्व में भारत ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार दी थी, लेकिन जब शास्त्री का निधन हुआ, तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति भी शोक में झुक गए थे।**

दो अक्टूबर को उस प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है, जिनकी सादगी, ऊँचे आदर्श और विनम्रता के लिए उन्हें जाना जाता है। 5 फुट 2 इंच के कद वाले, लेकिन अटूट हौसलों के मालिक थे लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब खान ने कभी शास्त्री की आवाज का मजाक उड़ाया था, लेकिन उनके निधन पर न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि सोवियत संघ का झंडा भी झुका और अयूब खान सबसे शोकाकुल लोगों में से एक थे।

1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध शास्त्री जी के कार्यकाल की एक अहम घटना थी, जिसमें उन्होंने सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया। युद्ध के चार दिन बाद रामलीला मैदान में अपने भाषण में उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, 'अयूब साहब अपने सैकड़ों टैंकों के साथ दिल्ली आने का इरादा रखते थे, तो हम

भी थोड़ा लाहौर की ओर घूम आए। उस समय वही आवाज, जिसका मजाक उड़ाया गया था, हजारों लोगों के सामने गूंज रही थी।

लाल बहादुर शास्त्री से पहले जवाहरलाल नेहरू को देश की आवाज माना जाता था। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त शंकर वाजपेयी ने बताया था कि नेहरू की मृत्यु के बाद अयूब खान दिल्ली नहीं आए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अब किससे बात की जाए। शास्त्री जी ने कहा, 'आप मत आइए, हम आ जाएंगे।' वह गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से लौटते वक्त कराची में थोड़ी देर रुके थे, लेकिन अयूब खान तब भी उनके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाए थे। 1965 के युद्ध ने पाकिस्तान की यह धारणा बदल दी। युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने अमेरिका के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने भारत को युद्ध से पीछे हटने की धमकी दी थी, अन्यथा गेहूं की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। शास्त्री जी ने तब देशवासियों से सप्ताह में एक दिन उपवास रखने की अपील की और पहले अपने परिवार से इसका पालन करवाया।

उनके आदर्श इतने ऊँचे थे कि 1963 में जब उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तो घर में बिजली का सीमित उपयोग करने लगे, क्योंकि वह सरकारी खर्च पर बिजली का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। ताशकंद सम्मेलन के दौरान सोवियत संघ के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोशियन ने उन्हें एक गर्म कोट दिया, लेकिन शास्त्री जी ने उसे अपने सहयोगी को दे दिया और खुद साधारण कोट में ठंड झेली।

11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही शास्त्री जी का निधन हो गया। उनके निधन के समय पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर के पास पहुंचे और कहा, 'यह वही व्यक्ति है, जो भारत और पाकिस्तान को एक कर सकता था।' जब उनका पार्थिव शरीर ताशकंद से भारत लाया जा रहा था, तो सोवियत, भारतीय और पाकिस्तानी झंडे झुके हुए थे। अयूब खान ने शास्त्री जी के ताबूत को कंधा दिया, और यह क्षण दोनों देशों के संबंधों में एक विशेष था।

**सांगानेर की खुली जेल में काम करने, परिवार के साथ रहने का मौका, कोई कैदी वाली वदी भी नहीं**

कल्पना कीजिए एक ऐसी जेल जहां कैदियों को तनखावा





के लिए बाहर काम करने का अवसर मिले, अपने परिवार के साथ रहने का मौका हो, और कैदी वर्दी पहनने की बाध्यता न हो, बस शाम तक वापस लौटकर उपस्थिति दर्ज करनी हो। यही है सांगानेर की खुली जेल, जहां कई कैदियों का जीवन बदला है।

### सांगानेर खुली की मुख्य बातें

- सांगानेर खुली जेल ने कई कैदियों को एक नई जिंदगी दी।
- सुप्रीम कोर्ट ने खुली जेल की जमीन लेने की कोशिश पर कड़ी नाराजगी जताई।
- सांगानेर मॉडल से प्रेरित होकर खुली जेलों की संख्या में वृद्धि हुई। कुछ ही दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सांगानेर की खुली जेल की जमीन लेने के प्रयास पर राजस्थान सरकार को फटकार लगाई थी। सांगानेर जेल को एक आदर्श जेल के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसी खुली जेल है जहां कैदियों को पारंपरिक जेल की चार दीवारों से बाहर निकलकर नया जीवन शुरू करने का मौका मिलता है। यहां वे काम कर सकते हैं, अपनी कमाई से गुजारा कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। यह मॉडल कैदियों को सुधारने और उन्हें समाज में फिर से शामिल करने में मदद करता है।

### सांगानेर में मिला नया जीवन

कई ऐसे कैदी हैं जिन्होंने सांगानेर में नई जिंदगी पाई। दस साल तक पारंपरिक जेल में रहने के बाद उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन सांगानेर जेल ने उन्हें एक नई शुरुआत का मौका दिया। वहां उन्होंने काम किया, परिवार के साथ समय बिताया, और फिर से जीना शुरू किया। सांगानेर जेल में न तो लोहे की सलाखें हैं, न ताले, और यहां की व्यवस्था विश्वास पर आधारित है। उनका कहना है कि वे अपने परिवार के साथ रह सकते थे, दिन में बाहर जा सकते थे और अपनी मजदूरी का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते थे। उनके अनुसार, यह बहुत बड़ा बदलाव था। अब वे चार महीने से जेल से बाहर हैं, लेकिन उनका मानना है कि खुली जेल में बिताए गए चार सालों ने उन्हें वास्तविक दुनिया में ढलने में मदद की। परिवार का समर्थन और जयपुर में अपने व्यवसाय के कारण उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया।

### सांगानेर जेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

सांगानेर मॉडल कई राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। हालांकि, हाल ही में इसे खतरा पैदा हो गया जब जयपुर विकास प्राधिकरण ने जेल की जमीन का एक हिस्सा अस्पताल को देने का प्रस्ताव

रखा। इस फैसले का कई विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। उनका मानना है कि सांगानेर मॉडल कैदियों के सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे बचाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप कर भूमि आवंटन पर रोक लगा दी है। इस प्रकार की भूमि का उपयोग प्रतिबंधित करना गलत संदेश देता है, क्योंकि सांगानेर को लंबे समय से एक आदर्श मॉडल माना जाता है।

### सुविधाओं का बाहरी लोगों द्वारा भी उपयोग

सांगानेर की खुली जेल यह दिखाती है कि जेलें केवल सजा देने के लिए नहीं, बल्कि कैदियों के सुधार और उन्हें समाज में फिर से शामिल करने के लिए होनी चाहिए। यह मॉडल अन्य जगहों पर भी लागू किया जाना चाहिए। सांगानेर जेल जयपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और इसमें लगभग 450 कैदी रहते हैं। इसे 1963 में विकसित किया गया था, और तब से कैदियों ने यहां आवास, स्कूल, खेल का मैदान और आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया है।

इन सुविधाओं का उपयोग कैदियों के परिवारों के साथ-साथ आस-पास के लोग भी करते हैं। खेल का मैदान सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के लिए उपयोग होता है, और स्कूल व आंगनवाड़ी में आस-पास के क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई करते हैं। जेल के नजदीक औद्योगिक क्षेत्र होने से कैदियों को काम मिल जाता है, और महिलाएं घरेलू कामगार के रूप में काम करती हैं।

### सांगानेर की सफलता

सांगानेर मॉडल की सफलता खुली जेलों की बढ़ती संख्या में दिखाई देती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में खुली जेलें शुरू करने का निर्देश दिया था। उस समय 60 खुली जेलें थीं, जो अब बढ़कर 152 हो गई हैं। राजस्थान में ही यह संख्या 22 से बढ़कर 52 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकर, जिन्होंने सांगानेर जेल का दौरा किया था, बताते हैं कि यहां भागने की कोई घटना नहीं हुई। यह दिखाता है कि सांगानेर मॉडल कारगर है।

# आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा, जानिए योजना से किसे क्या-क्या फायदा होगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। इस निर्णय से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त हो सकेगा। केंद्र सरकार ने यह अहम कदम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाया है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। इस योजना के विस्तार के लिए कैबिनेट की सहमति दी गई है।



## आइए पहले जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्या है।

भारत सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूपीएसी) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य सभी को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं—पहला, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, और दूसरा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (प्रधानमंत्री-जय)। 23 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी।

## अब जानते हैं कि सरकार ने अभी क्या निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार को स्वीकृति दी है। अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस योजना का कवरेज बढ़ाने की घोषणा की थी। अब इस निर्णय के अनुसार, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा, जिसका लक्ष्य है कि छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाए।

## आयुष्मान भारत योजना का विस्तार क्यों हुआ और इससे किसे लाभ मिलेगा?

सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल कर लिया है। इस फैसले से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिक, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को नया कार्ड जारी किया जाएगा। जो पहले से इस योजना में शामिल हैं, उनके लिए अलग से पांच लाख रुपये का टॉप-अप कवर मिलेगा, लेकिन

यह कवर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं किया जा सकेगा।

## योजना में लाभ किस आधार पर दिया जाता है?

आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। योजना के तहत SECC & 2011 जनगणना के तहत पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है। यह योजना पूरी तरह से सरकारी वित्तपोषित है, और इसका खर्च केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है।

## क्या योजना का विस्तार पहले भी हुआ है?

योजना का लाभ समय-समय पर विस्तारित किया गया है। शुरुआत में 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को शामिल किया गया था। बाद में 2022 में इसे बढ़ाकर 12 करोड़ परिवारों तक कर दिया गया। इसके अलावा, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी यह योजना विस्तारित की गई थी। अब इसे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए बढ़ाया गया है।

## आयुष्मान भारत योजना के लाभ

यह योजना प्रति परिवार को हर साल 5,00,000 रुपये तक का कैशलेस कवर प्रदान करती है। इसका लाभ पूरे परिवार द्वारा लिया जा सकता है। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है और पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया जाता है। इसमें 874 पैकेज और 1592 प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसका लाभ सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है।

## योजना में होने वाले खर्च

- टेस्ट, उपचार और परामर्श
- अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद की देखभाल
- दवा और चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं
- सर्जरी और उपचार सेवाएं
- अस्पताल में रहने की सुविधाएं

# विवादों में रहीं जस्टिस वक्टोरिया गौरी बनी सुप्रीम कोर्ट की स्थायी जज

**जस्टिस एलसी वक्टोरिया गौरी पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं। 2023 में जब उन्हें मद्रास हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया जा रहा था, तो उनका विरोध हुआ था।**

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के पांच अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की। इससे पहले, मद्रास हाईकोर्ट कॉलेजियम ने 29 अप्रैल 2024 को इन जजों को स्थायी बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था।

इस सिफारिश को मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मंजूरी मिली, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज से परामर्श के बाद अंतिम निर्णय लिया गया। जस्टिस वक्टोरिया गौरी ने मदुरै के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की और मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गौरी ने कॉलेज के दिनों में ही भाजपा से जुड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने हाल ही में बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा देने की बात स्वीकार की है। उन्होंने 1995 में एक वकील के रूप में पंजीकरण कराया और 1997 में कन्याकुमारी में अपनी खुद की फर्म, वी-विकट्री लीगल एसोसिएट्स की शुरुआत की।

स्थायी जजों में शामिल जजों में तीन महिला जजें— जस्टिस एलसी वक्टोरिया गौरी, जस्टिस रामचंद्रन कलैमथी, और जस्टिस के. गोविंदराजन थिलकावडी हैं। इसके अलावा, जस्टिस पीबी बालाजी और जस्टिस केके रामकृष्णन भी इस सूची में शामिल हैं।

जस्टिस एलसी वक्टोरिया गौरी पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं। 2023 में जब उन्हें मद्रास हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया जा रहा था, तो उनका विरोध हुआ था। 21 वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सिफारिश की फाइल को वापस करने की अपील की थी, जिसमें वक्टोरिया गौरी की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। वकीलों ने दावा किया था कि वक्टोरिया गौरी बीजेपी नेता हैं और उनके कुछ बयानों को अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ बताया था। वकीलों ने आरोप लगाया था कि उनके विचार और धार्मिक कट्टरता

उन्हें हाईकोर्ट के जज के तौर पर अयोग्य बनाते हैं।

वक्टोरिया गौरी के राजनीतिक जुड़ाव पर सवाल उठ चुके हैं। उन्होंने वकालत में 21 साल का अनुभव अर्जित किया है और तमिलनाडु के नागुरकोइल में 1973 में जन्मी हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि उन्होंने जून 2020 में बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, उनकी ट्विटर प्रोफाइल पर श्चौकीदार वक्टोरिया गौरी लिखा था, लेकिन अब उनका अकाउंट सक्रिय नहीं है। वकीलों ने विरोध में आरएसएस द्वारा होस्ट किए गए यूट्यूब चैनल पर उनके दो इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसमें एक इंटरव्यू में गौरी ने ईसाइयों और इस्लाम को लेकर विवादास्पद टिप्पणियां की थीं। इन टिप्पणियों को लेकर विवाद पैदा हुआ था।



# न्यायपालिका को अपराधी नहीं, पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट का अपना पक्ष हो सकता है लेकिन सभी आपराधिक मामलों के समय यह कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। अपराध करने वाला अगर ताकतवर हो तो वह कानून को अपने हिसाब से 'खरीद' लेता है। अपना सही-गलत बचाव करने के लिए वकीलों की पूरी फौज कोर्ट में उतार देता है।



## संजय सक्सेना, लखनऊ

यह बात समझ से परे है कि जो लोग जघन्य अपराध करते हैं? छोटी-छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते समय सरकार पूरी तरह से कानून का पालन करे। तर्क दिया जाता है कि अपराध कोई एक व्यक्ति करता है तो उसके पूरे परिवार को इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े। ऐसे तर्क देने वालों को समझना चाहिए कि जब किसी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म या परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई आपराधिक वारदात होती है तो उसका खामियाजा जब पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, तो फिर अपराधी को इस आधार पर कैसे छूट दी जा सकती है कि उसके किये अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। बात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की हो रही है जिसमें उसने राज्य सरकारों द्वारा की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठाया था। सुप्रीम कोर्ट का अपना

पक्ष हो सकता है लेकिन सभी आपराधिक मामलों के समय यह कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। अपराध करने वाला अगर ताकतवर हो तो वह कानून को अपने हिसाब से 'खरीद' लेता है। अपना सही-गलत बचाव करने के लिए वकीलों की पूरी फौज कोर्ट में उतार देता है। क्या यह सही नहीं है कि आज भी जेलों में छोटे मोटे अपराध करने वालों को इसलिये जमानत नहीं मिल पा रही है क्योंकि वह आर्थिक रूप से सबल नहीं हैं। उनका दर्द कोर्ट की चौखट तक पहुंच ही नहीं पाता है। सुप्रीम कोर्ट इस बात की व्याख्या कभी क्यों नहीं करता है कि एक मुकदमे में वादी-प्रतिवादी की तरफ से कितने अधिवक्ता बहस कर सकते हैं।

यह सच नहीं है कि सरकार हर एक अपराधिक मामले में बुलडोजर लेकर खड़ी हो जाती है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया जाता है जैसे सरकार बहुत बड़ी कसूरवार हो। खासकर योगी सरकार पर तो यह भी आरोप लगते हैं

कि वह मुस्लिमों के खिलाफ ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई करते हैं। ऐसी बातें करने वाली कानून की आड़ में अपने अपराध पर पर्दा डालने का काम करते हैं। बता दें कई राज्यों में प्रशासन द्वारा आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने पर 02 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था। कोर्ट का सवाल था कि कानून में तय प्रक्रिया का पालन किये बगैर किसी का घर कैसे ढहाया जा सकता है। सिर्फ किसी के अभियुक्त होने पर उसका घर कैसे ढहाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने बगैर नोटिस के आरोपियों के घर ढहाने की शिकायत पर कहा कि अगर वह दोषी भी है तो भी कानून में तय प्रक्रिया के बगैर उसका घर नहीं ढहाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह कथन समानांतर सरकार चलाने जैसा नजर आता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का संकेत देते हुए सभी पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं। यह कहते समय सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी के उस बयान पर भी गौर फरमा लेता तो ज्यादा अच्छा होता जिमसे पीएम ने सुप्रीम कोर्ट के एक कार्यक्रम में उससे महिलाओं से जुड़े मामले जल्द से जल्द निपटाने की उम्मीद जताई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद थे।

हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह के आदेश कोर्ट जारी करती है उससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता ही है। पूरा देश अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है इस के लिये सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने कभी उतने सख्त कदम नहीं उठाये जितने अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में उठाये जाते हैं। कोई रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके बस्तियां बसा लेता है तो कोई नजूल की जमीन हाथिया कर बेच देता है। कोर्ट के आदेश से लगता है कि वह एक बेगुनाह को सजा न हो इसके लिये 199 गुनहगारों के प्रति नरम रवैया अख्तियार करने से संकोच नहीं करता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी ढंग से निर्माण ढहाए जाने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कानून की तय प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाती है। किसी अपराध में आरोपित होना कभी भी अचल संपत्ति के ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता। मामले में 17 सितंबर को फिर सुनवाई होगी।

बता दे बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ ये टिप्पणियां और निर्देश न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने जमीयत उलमा ए हिंद व अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए थे। जमीयत ने याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में गैर कानूनी ढंग से आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा है कि विभिन्न राज्यों में बुलडोजर इंसफ का खतरनाक चलन बढ़ा है। इसमें समुदाय विशेष को और वंचित वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और फारुख रशीद पेश हुए, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की। उत्तर प्रदेश सरकार की

**यह सच नहीं है कि सरकार हर एक अपराधिक मामले में बुलडोजर लेकर खाड़ी हो जाती है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया जाता है जैसे सरकार बहुत बड़ी कसूरवार हो। खासकर योगी सरकार पर तो यह भी आरोप लगते हैं कि वह मुस्लिमों के खिलाफ ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई करते हैं।**

ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में गत नौ अगस्त को ही हलफनामा दाखिल कर दिया था और उस हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में आरोपी है तो उसका घर ढहाए जाने का यह आधार कतई नहीं हो सकता। कोई भी अचल संपत्ति सिर्फ, इस आधार पर नहीं ढहाई जा सकती कि व्यक्ति किसी अपराध में आरोपी है। मेहता ने कहा कि अचल संपत्ति म्युनिसिपल अधिनियम और विकास प्राधिकरणों के अधिनियम के उल्लंघन पर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही ढहाई जाती है। पीठ ने मेहता से कहा कि अगर आप ये स्थिति स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कोर्ट आपका बयान दर्ज करके पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा। मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता इस तरह से मामले को पेश कर रहे हैं, जैसे कि कोई किसी अपराध में आरोपी होता है तो उसका मकान ढहा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। वह दिखा सकते हैं। अर्थांरिटीज ने मकान ढहाए जाने से बहुत पहले नोटिस जारी किया था। निर्माण अवैध होने पर ही ढहाया जाता है।

पीठ ने भी स्पष्ट किया कि वह किसी अवैध निर्माण या सड़क पर अतिक्रमण को संरक्षित नहीं करेंगे, लेकिन इस संबंध में दिशा-निर्देश होने चाहिए। जस्टिस

गवई ने कहा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वह आरोपी है। अगर वह दोषी भी है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अवैध निर्माण पर भी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई हो सकती है। मेहता ने कहा कि इस मामले में जिनके घर ढहे हैं, उनकी जगह यहां याचिका जमीयत ने दाखिल की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का हलफनामा देखते हुए कोर्ट को यह मामला बंद कर देना चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता जमीयत की ओर से पेश वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया। दुष्यंत दवे ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक जगह का नहीं है, यह व्यापक मुद्दा है और कोर्ट को इस पर सुनवाई करके दिशा-निर्देश तय करने चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भी कमियों का फायदा न उठा पाए। निर्माण अवैध है तो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन इस आधार पर किसी का घर गिरा दिया जाए तो यह तरीका सही नहीं है। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने भी बहस की। दवे और सिंह ने कहा कि यहां कुछ मामले ऐसे हैं, जिसमें किराएदार के आरोपी होने पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सभी लोग अपने अपने सुझाव दाखिल करें, ताकि कोर्ट इस संबंध में पूरे देश के लिए उचित दिशा-निर्देश तय कर सके। अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट अपराधियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो इस पर तो चिंतित दिखा लेकिन पूरी सुनवाई के दौरान उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे इस बात का अहसास होता कि कोर्ट की संवेदनाए पीड़ित पक्ष के साथ भी जुड़ी हुई हैं, जो चिंताजनक है। जब किसी सरकार में अपराध बढ़ते हैं तो तमाम कोर्ट उसको कटघरे में खड़ा करता है, लेकिन जब अपराध नियंत्रण के लिये कोई कार्रवाई की जाती है तो वह सरकार को ही कार्रवाई पर उंगली उठाती है।

# अब 3D मेटावर्स पर दिखेंगे लखनऊ-प्रयागराज के पर्यटन स्थल, प्रदेश के 100 प्रमुख स्थलों का होगा वर्चुअल भ्रमण

लखनऊ और प्रयागराज के पर्यटन स्थलों को 3डी मेटावर्स पर दिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की इस परियोजना के तहत, इन शहरों की 1,500 प्रमुख जगहों का 3डी मेटावर्स अनुभव तैयार किया जाएगा। इसके लिए, इन जगहों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है।



उत्तर प्रदेश सरकार अब डिजिटल तकनीक के जरिए राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर लखनऊ और प्रयागराज के 1500 प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3ड मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाएगा। योगी सरकार की पहल पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3ड मेटावर्स प्लेटफॉर्म और ऑडियो टूर पोर्टल के जरिए पर्यटकों के लिए डिजिटल रूप से सुलभ बनाया जा रहा है। इस अत्याधुनिक परियोजना के तहत लखनऊ और प्रयागराज के 1500 प्रमुख स्थलों का 360-डिग्री पैनोरमिक डेटा एकत्र कर, उन्हें जियो-रेफरेंस मैप्स से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, क्यूआर



कोड इनेबल्ड ऑडियो टूर की सुविधा से प्रदेश के 100 प्रमुख स्थलों का वर्चुअल

भ्रमण भी जल्द ही संभव होगा। मेटावर्स के जरिए वर्चुअल अनुभव मुख्यमंत्री योगी



आदित्यनाथ की मंशा अनुसार, पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण लखनऊ और प्रयागराज शहरों की 1500 प्रमुख जगहों का 3वें मेटावर्स अनुभव तैयार किया जाएगा। इसके लिए 360-डिग्री पैनोरमिक डेटा संकलित कर उसे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इन जगहों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है, ताकि पर्यटक आभासी दुनिया में इन जगहों का सजीव अनुभव कर सकें। एक वेब और मोबाइल एप्लिकेशन का भी निर्माण किया जाएगा, जो पर्यटकों को लखनऊ और प्रयागराज के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का वर्चुअल टूर उपलब्ध कराएगा। 1500 लैंडमार्क्स का 360-डिग्री पैनोरमिक डेटा संग्रहण लखनऊ और प्रयागराज में 1500 महत्वपूर्ण स्थलों के 360-डिग्री पैनोरमिक दृश्य संकलित किए जाएंगे। इन स्थलों में ऐतिहासिक धरोहरें, मंदिर, बाजार, और पर्यटन स्थल शामिल होंगे। प्रमुख हेरिटेज स्थानों में लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी हब और प्रयागराज के कुंभ मेले के घाटों, हनुमान मंदिर, और अन्य धार्मिक स्थलों को डिजिटल रूप में दर्शाया जाएगा। इस

वर्चुअल टूर के जरिए पर्यटक इन जगहों का आभासी दौरा कर सकेंगे, जिससे पर्यटन का अनुभव नए आयाम तक पहुंच जाएगा। 100 स्थलों के लिए ऑडियो टूर की सुविधा पर्यटकों के लिए क्यूआर कोड इनेबल्ड ऑडियो टूर पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 100 प्रमुख स्थलों पर ध्वनि आधारित भ्रमण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, श्रावस्ती, लखनऊ और आगरा सहित प्रमुख शहरों के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर यह ऑडियो टूर होगा। पर्यटक अपने स्मार्टफोन के जरिए क्यूआर कोड स्कैन कर इन स्थलों की जानकारी ऑडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। प्रयागराज के पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद म्यूजियम, चंद्रशेखर आजाद पार्क, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और कपिलवस्तु के स्तूप जैसे कई महत्वपूर्ण स्थलों को इस सुविधा में शामिल किया जाएगा। पर्यटन को नया आयाम देने की तैयारी उत्तर प्रदेश को देश का 'मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन' बनाने की दिशा में यह कदम न केवल पर्यटन के विकास में मदद करेगा, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक

धरोहर को भी एक नया आयाम देगा। यह परियोजना पर्यटकों को उनके घर बैठे प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का आभासी अनुभव कराएगी और उन्हें वास्तविकता के करीब लाने का प्रयास करेगी। ऑडियो टूर और मेटावर्स जैसी नई तकनीकें पर्यटन को और अधिक सुलभ और आकर्षक बनाएंगी। अत्याधुनिक तकनीक से सजीव चित्रण परियोजना के तहत सभी स्थलों का डेटा और कंटेंट इस तरह से तैयार किया जाएगा कि पर्यटक उन स्थानों का अनुभव वास्तविक रूप से कर सकें। इस तकनीक से न केवल पर्यटन स्थलों का बेहतर प्रचार-प्रसार होगा, बल्कि देश-विदेश के पर्यटक भी उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ सकेंगे। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में पर्यटन को डिजिटल युग में ले जाने की एक बड़ी पहल है। लखनऊ और प्रयागराज के प्रमुख स्थलों का 3वें मेटावर्स और क्यूआर कोड इनेबल्ड ऑडियो टूर पर्यटकों को एक अनोखा और समृद्ध अनुभव प्रदान करेगा। इससे न केवल राज्य के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।

# उत्तर प्रदेश: शिक्षक भर्ती परीक्षा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था।



उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा विवाद एक नया मोड़ ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश अभी लागू नहीं होगा और इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने पक्षकारों से अधिकतम सात पन्नों में अपनी दलीलें प्रस्तुत करने को कहा है और अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2020 और 2022 की चयन सूची को रद्द कर दिया था और राज्य सरकार को 2019 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर नई मेरिट सूची जारी करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा था।

इस विवाद की जड़ें अखिलेश यादव सरकार के समय तक जाती हैं, जब 1,37,000 शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस समायोजन को रद्द कर दिया और योगी सरकार को इन पदों पर नई भर्ती का आदेश दिया। इसके बाद 2018 में 68,500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई और दूसरे चरण में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई। आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह मात्र 3.86 प्रतिशत आरक्षण मिला यानी ओबीसी वर्ग को 18598 सीट में से मात्र 2637 सीट मिलीं। जबकि उस वक्त सरकार का कहना था कि करीब 31 हजार ओबीसी वर्ग के लोगों की



नियुक्ति की गई। सरकार के इस बयान पर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली-1981 का तथा आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के जिन 31 हजार लोगों को नियुक्ति दी गई है, उनमें से करीब 29 हजार अनारक्षित कोटे से सीट पाने के हकदार थे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें 29 हजार ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण के दायरे में जोड़ना ही नहीं चाहिए।

लेकिन इस भर्ती में आरक्षण नियमों को सही से लागू न करने का आरोप लगा। उम्मीदवारों का कहना था कि ओबीसी और एससी वर्ग को आरक्षित सीटों का पूरा लाभ नहीं मिला। ओबीसी उम्मीदवारों को सिर्फ 3.86 प्रतिशत आरक्षण मिला, जबकि उन्हें 27 प्रतिशत मिलना चाहिए था। इसी तरह एससी वर्ग को भी 21 प्रतिशत की जगह सिर्फ 16.6 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। अभ्यर्थियों ने इन मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत की थी। इस भर्ती में 19,000 सीटों को लेकर विवाद होने के कारण मामले ने तूल पकड़ा, और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला लेगा।

# कहीं कश्मीर की सियासत की 'मायावती' न बन जाएं महबूबा मुफ्ती

दस साल बाद हो रहा यह चुनाव कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व का फैसला करेगा।

कश्मीर की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की भूमिका बदलती दिख रही है। उनकी राजनीतिक स्थिति यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जैसी होती नजर आ रही है। महबूबा अब अपनी बेटी इलतिजा मुफ्ती को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं, और उन्हें कश्मीर घाटी में 5 से 7 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यह चुनाव कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व का फैसला करेगा। दस साल बाद हो रहे इस चुनाव से यह तय होगा कि कश्मीर का अगला राजनीतिक राजा कौन होगा। चाहे वह महबूबा हों, उमर अब्दुल्ला, अपनी पार्टी के नेता अल्लाफ बुखारी हों, या पीपुल्स कांफ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन। इस चुनाव में जमात, जो कभी आतंकवाद को बढ़ावा देती थी, अपनी वास्तविक राजनीतिक ताकत देखेगी। अभी यहां सभी दल अपनी दिशा तय करने में लगे हुए हैं।

## यूपी, बिहार और महाराष्ट्र की पार्टियां भी मैदान में हैं

जम्मू-कश्मीर में सिर्फ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां ही नहीं, बल्कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की पार्टी जेडीयू, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और महाराष्ट्र की आरपीआई (अठावले) भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा आरएलडी, एनसीपी, भीम सेना, सीपीएम और आम आदमी पार्टी भी चुनाव में भाग ले रही हैं। करीब 20 पार्टियां इस चुनाव में ताल ठोक रही हैं।

## कांग्रेस और एनसी की नूराकुशी

यह चुनावी परिदृश्य अनूठा है क्योंकि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन होते हुए भी, दोनों पार्टियां कई जगहों पर एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। बनिहाल, डोडा, भदरवाह, देवसर, सोपोर और बारामूला में दोनों एक-दूसरे के सामने खड़ी हैं।

## देखने को मिल रही है यूपी की राजनीतिक झलक

इस बार कश्मीर की राजनीति में यूपी की राजनीतिक झलक भी देखने को मिल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरह, नेशनल कांफ्रेंस के उमर अब्दुल्ला भी आक्रामक और हाजिरजवाब दिख रहे हैं। वहीं, पहली बार जेल से यूपी विधानसभा पहुंचे हरिशंकर तिवारी की तरह सांसद बने रशीद इंजीनियर का भी दबदबा है। भले ही उनकी पार्टी चुनाव में खास प्रदर्शन न कर पाए, लेकिन वे कुछ खास नेताओं का समीकरण बिगाड़ सकते हैं।

## जमात का चुनावी प्रभाव

कश्मीर के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि जमात ने आतंकवाद से किनारा कर लोकतंत्र का रास्ता चुना है। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। इस बदलाव का असर कश्मीर में देखा जा सकता है, जहां अब रात दस बजे तक बारामूला से कुपवाड़ा तक बाजार खुले रहते हैं। जमात भले ही चुनाव में बड़ा प्रदर्शन न करे, लेकिन कई सीटों पर वह दिग्गज नेताओं की जमानत जप्त करा सकती है।





## 95 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले ताजिकिस्तान में हिजाब पर रोक, अवैध मस्जिदों में खुले कैफे

द डिलोमेट की एक रिपोर्ट की मानें तो ताजिकिस्तान की सरकार ने बीते कुछ सालों के भीतर दो हजार से भी ज्यादा मस्जिदें बंद करते हुए उन्हें कैफे, सिनेमाघर, फैंक्ट्री या सोशल वर्क सेंटरों में बदल दिया। इसका मकसद धार्मिक प्रैक्टिस को कट्टरता से दायरे से बाहर लाना था।

अफगानिस्तान में हाल ही में एक आदेश जारी किया गया, जिसमें धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने महिलाओं के बोलने और गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका कहना है कि महिलाओं की आवाज "घनिष्ठ" होती है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर चुप रहना चाहिए। तालिबान के आने के बाद से देश में चरमपंथ बढ़ गया है। वहीं, 90 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाले ताजिकिस्तान में कट्टरता के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। जहां अधिकतर इस्लामी देश महिलाओं के लिए विशेष ड्रेस कोड और नियमों की बात करते हैं, वहीं ताजिकिस्तान बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। यहां की सरकार ने हिजाब पहनने और दाढ़ी बढ़ाने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, बच्चों को सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों में

शामिल होने की अनुमति नहीं है। सरकार देश में मस्जिदों को भी बंद कर रही है और उनकी जगह व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कर रही है।

### हिजाब पर कानूनी प्रतिबंध

ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन लगातार हिजाब को "विदेशी पोशाक" कहते रहे हैं और सार्वजनिक





स्थानों पर इसे पहनने का विरोध करते रहे हैं। उनके सत्ता में आने के बाद से ही हिजाब पर अनौपचारिक रूप से प्रतिबंध देखने को मिला, हालांकि उस समय कोई नियम या सजा तय नहीं थी। अब लगभग दो महीने पहले, ताजिकिस्तान ने संसद में प्रस्ताव पास करके हिजाब पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत हिजाब पहनने, बेचने-खरीदने और इसे बढ़ावा देने पर भी प्रतिबंध है।

### नियम तोड़ने पर जुर्माना

यह प्रतिबंध केवल कहने भर का नहीं है। अगर कोई महिला इस नियम का उल्लंघन करती है तो उस पर लगभग 700 डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी महिला ऐसा करती है तो उसे और भी अधिक जुर्माना देना होगा। हिजाब के अलावा ताजिक सरकार ने कई धार्मिक प्रथाओं पर भी रोक लगाई है। सबसे चौंकाने वाला फैसला मस्जिदों के बारे में था।

### मस्जिदों को कैफे में बदला गया

“द डिप्लोमेट” की एक रिपोर्ट के अनुसार, ताजिकिस्तान सरकार ने पिछले कुछ सालों में दो हजार से

अधिक मस्जिदों को बंद करके उन्हें कैफे, सिनेमाघर, फ़ैक्ट्री या सामाजिक कार्य केंद्रों में बदल दिया। इसका उद्देश्य धार्मिक प्रथाओं को कट्टरता से बाहर लाना था। राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने यह कदम धीरे-धीरे उठाया। पहले उन मस्जिदों को नोटिस जारी किया गया जिनके पास पंजीकरण नहीं था। बाद में, अनाधिकृत धार्मिक स्थानों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया।

### ऐसे फैसले क्यों ले रही है सरकार?

2020 में, ताजिकिस्तान की कुल आबादी में 96 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम थे, इसलिए इस तरह के फैसले चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन के इन कदमों के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है— धार्मिक कट्टरता को कम करते हुए बाकी दुनिया से जुड़ना। 90 के दशक में सोवियत संघ (अब रूस) से अलग होने के बाद, ताजिकिस्तान में कई कट्टरपंथी ताकतें उभरीं, जो आपस में लड़ाई करके सत्ता हासिल करना चाहती थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता के लगभग छह साल तक देश में युद्ध चलता रहा।

### चरमपंथी दलों पर प्रतिबंध

इसके बाद, रहमोन ने कट्टरपंथ पर नियंत्रण के लिए संसद के माध्यम से कई कदम उठाए। हालांकि इसके लिए उन्हें भीतर और बाहर विरोध का सामना करना पड़ा।

जैसे, अपने ही देश के कट्टरपंथी संगठन इस्लामिक पुनर्जागरण पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया। कई अन्य संगठनों को भी प्रतिबंधित किया गया जिन्हें पहले राजनीतिक दलों का दर्जा मिला हुआ था। दूसरे देशों ने भी रहमोन पर धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया, लेकिन इसके बावजूद वे सत्ता में बने रहे और बदलाव करते रहे।

### महिलाओं की स्थिति में सुधार

धार्मिक कट्टरता पर कड़ी कार्रवाई के बाद से महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। उन्हें राजनीति और प्रशासन में जगह मिली है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आया। यूनिसेफ की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, देश की 40 प्रतिशत से अधिक महिलाएं अभी भी घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं।

# भारत में मंकीपॉक्स का पहला मरीज दिल्ली में मिला

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को अस्पताल का आकस्मिक दौरा किया और मंकीपॉक्स और डेंगू के मामलों से निपटने के लिए अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया।



दिल्ली में मंकीपॉक्स का पहला पुष्टि किया गया मामला सामने आया है, जिसमें 26 वर्षीय एक पुरुष, जो हरियाणा के हिसार से है, को लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को अस्पताल का आकस्मिक दौरा किया और मंकीपॉक्स और डेंगू के मामलों से निपटने के लिए अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया।

मरीज की यात्रा इतिहास एक ऐसे देश से जुड़ा है जहां मंकीपॉक्स का प्रसार अभी भी जारी है। उसे एलएनजेपी अस्पताल के विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, मरीज के केवल जननांग क्षेत्र में घाव और शरीर पर चकत्ते हैं, लेकिन उसे बुखार नहीं है। शनिवार को उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मरीज एक युवा व्यक्ति है, जिसने हाल ही में मंकीपॉक्स प्रभावित देश की यात्रा की है और उसे तृतीयक देखभाल के आइसोलेशन में रखा गया है। मरीज की स्थिति स्थिर है और उसे कोई अन्य



बीमारी या सह-रुग्णता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जनता को आश्वासन दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंकीपॉक्स सीधे संपर्क से फैलता है, न कि हवा के जरिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले को 'एकल' के रूप में वर्गीकृत किया है और कहा कि आम जनता के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है। मंकीपॉक्स एक वायरस जनित रोग है जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से फैलता है। यह सीधे संपर्क, शारीरिक संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से फैल सकता है। हालांकि, मंकीपॉक्स की गंभीरता

आमतौर पर हल्की होती है और अधिकांश लोग बिना किसी बड़ी जटिलता के ठीक हो जाते हैं। एलएनजेपी अस्पताल और अन्य चिकित्सा संस्थानों में विशेष आइसोलेशन वार्ड और संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संक्रमण से बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और आम जनता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

# हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद पर बवाल

इस घटना के चलते शिमला के मॉल रोड जैसी प्रमुख जगहों पर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला और कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं।



सितंबर 2024 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक मस्जिद को लेकर बढ़ते विवाद ने राज्य में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी। मस्जिद निर्माण को लेकर स्थानीय समुदायों के बीच मतभेद ने धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया है, जिसके कारण हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस घटना के चलते शिमला के मॉल रोड जैसी प्रमुख जगहों पर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला और कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं।

## विवाद की शुरुआत

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मस्जिद के निर्माण को लेकर कुछ स्थानीय हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। उनका दावा था कि मस्जिद का निर्माण अवैध है और इससे क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। मस्जिद के निर्माण के समर्थक, जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे, का तर्क था कि यह धार्मिक स्थल उनकी समुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। इस मसले पर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ने लगा, और धीरे-धीरे मामला राजनीतिक रंग लेने लगा।

## प्रदर्शन और बवाल

विवाद के बाद हिंदू संगठनों ने शिमला में



विरोध प्रदर्शन किया, जो धीरे-धीरे हिंसक हो गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने मॉल रोड पर दुकानें बंद कर दीं और जगह-जगह आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं। शिमला के कई प्रमुख हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

## प्रशासन की प्रतिक्रिया

स्थानीय प्रशासन ने विवाद को लेकर सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। शिमला के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, प्रशासन ने क्षेत्र

में धारा 144 लागू कर दी है, ताकि बड़े जमावड़े पर रोक लगाई जा सके और स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

## राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

इस मस्जिद विवाद ने राज्य की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह धार्मिक मुद्दों को सही तरीके से नहीं संभाल पा रही है, जिससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। वहीं, सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष पर मामले को भड़काने और राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है। विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने इस मुद्दे पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है।

## अविष्य की दिशा

इस घटना ने हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिक सदभाव और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को एक बार फिर से प्रमुखता दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के विवादों से राज्य की शांति और सौहार्द पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रशासन को जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकालने की जरूरत है, ताकि राज्य में शांति बहाल की जा सके और सांप्रदायिक तनाव को कम किया जा सके।

# भारत ने MSCI उभरते बाजार सूचकांक में चीन को पछाड़ा



यह बदलाव भारत की आर्थिक मजबूती और बाजार की स्थिरता को दर्शाता है, जो वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है।

सितंबर 2024 में भारत ने मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (MSCI) उभरते बाजार सूचकांक में चीन को पछाड़ते हुए सबसे बड़ा बाजार हिस्सा (वेटेज) हासिल किया। MSCI इंडेक्स ग्लोबल निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है, जो उन्हें विभिन्न देशों के शेयर बाजारों में निवेश के अवसरों का आकलन करने में मदद करता है। इस सूचकांक में भारत का हिस्सा अब 22.27 प्रतिशत हो गया है, जबकि चीन का 21.58 प्रतिशत रह गया है। यह बदलाव भारत की आर्थिक मजबूती और बाजार की स्थिरता को दर्शाता है, जो वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है।

## भारत की मजबूत स्थिति का कारण

भारत का MSCI उभरते बाजार सूचकांक में चीन को पीछे छोड़ना कई कारणों पर आधारित है। सबसे प्रमुख कारण है भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, जो वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने भी भारत की विकास दर को लेकर सकारात्मक भविष्यवाणी की है, जो लगभग 7 प्रतिशत तक है। इसके अलावा, भारत की आर्थिक नीतियां, डिजिटल इंडिया अभियान, स्टार्ट-अप का विकास, और उत्पादन में वृद्धि ने भी

भारतीय बाजार को मजबूती दी है। चीन के मुकाबले भारत में विदेशी निवेशकों के लिए एक स्थिर और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध है। जबकि चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, विशेष रूप से COVID-19 के बाद, और अमेरिका के साथ व्यापार तनाव ने चीन की आर्थिक वृद्धि पर दबाव डाला है। चीन में बढ़ते जोखिमों और राजनीतिक अस्थिरता के बीच, वैश्विक निवेशकों का झुकाव भारत की ओर अधिक हो रहा है।

## वैश्विक निवेशकों के लिए भारत का आकर्षण

भारत की युवा जनसंख्या, तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास, और डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते कदम भी निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। इसके अलावा, भारत का सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं, वैश्विक निवेशकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। भारतीय शेयर बाजार ने हाल के वर्षों में भी मजबूती दिखाई है, जो वैश्विक निवेशकों के विश्वास को और बढ़ाता है। इसके विपरीत, चीन की सुस्त आर्थिक वृद्धि और सरकारी नियंत्रण की नीतियों ने विदेशी निवेशकों में असमंजस पैदा किया है।

इसके अलावा, चीन की रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर में आई अस्थिरता भी विदेशी निवेशकों के लिए चिंताजनक रही है। इन चुनौतियों के बीच, भारत एक

स्थिर और सुरक्षित निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है।

## भारतीय बाजारों की भविष्य की दिशा

भारत का MSCI में चीन से आगे निकलना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत अपनी आर्थिक नीतियों को सुदृढ़ रखता है और सुधारों को जारी रखता है, तो आने वाले वर्षों में यह स्थिति और मजबूत हो सकती है। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयास भारत की वैश्विक स्थिति को और सशक्त कर सकते हैं। भारत के इस प्रदर्शन से यह भी स्पष्ट होता है कि उभरते बाजारों में अब चीन का वर्चस्व कम हो रहा है, और अन्य अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से भारत, वैश्विक निवेश परिदृश्य में अपनी जगह बना रही हैं।

भारत के पास अपनी आर्थिक शक्ति को और मजबूत करने का अवसर है, और यह संकेत है कि भविष्य में भारत वैश्विक निवेश का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। भारत की इस उपलब्धि से न केवल उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि वह एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भी उभर रहा है।

# IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया



अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने सितंबर 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाते हुए इसे 7 प्रतिशत तक कर दिया है। यह अनुमान पहले 6.8 प्रतिशत था, लेकिन IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था में जारी मजबूती, औद्योगिक वृद्धि, और ग्रामीण खपत में सुधार के कारण इसे बढ़ाया है। IMF के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद स्थिर और सकारात्मक प्रगति कर रही है, जो इसे अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभार रही है।

## आर्थिक वृद्धि के कारण

प्ले ने भारत की बढ़ती घरेलू मांग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती खपत और शहरी क्षेत्रों में बढ़ते निवेश को मुख्य कारण बताया है। इसके अलावा, सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधार, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं (PLI), और ढांचागत विकास में निवेश से भी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिला है। आईटी सेक्टर, सेवा उद्योग, और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी लगातार सुधार हो रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

## वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूती

दुनियाभर में मंदी और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में धीमी प्रगति के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था अपने विकास पथ पर

बनी हुई है। IMF ने यह भी कहा कि भारत के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार करने की क्षमता है और इसने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में भी सफलता प्राप्त की है। भारत की सरकार द्वारा लगातार बुनियादी ढांचे में निवेश और निजी निवेश को आकर्षित करने की नीतियां भी इस वृद्धि के पीछे एक प्रमुख कारक हैं।

## भविष्य की दिशा

IMF का यह अनुमान इस बात का संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनी रहेगी। आगामी वर्षों में, यदि भारत अपनी नीतियों में सुधार जारी रखता है, तो यह उभरते बाजारों में एक बड़ी शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत के आर्थिक विकास के मजबूत बने रहने की संभावना है, जिससे इसका

वैश्विक महत्व बढ़ेगा।

भारत की इस वृद्धि से न केवल देश के नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, बल्कि वैश्विक बाजार में भी इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ रही है। प्ले के इस बढ़े हुए अनुमान से यह भी स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।



# राजस्थान का भूतिया किला

## जहां शाम होते ही पसर जाता है सन्नाटा

**आज हम ऐसे ही एक वीराने का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जो सदियों से एक अनसुलझी पहली बना हुआ है। राजस्थान के अलवर जिले के अजबगढ़ गांव में ऐसी शापित हवेलियां हैं जो एक ही दिन में वीरान हो गई थीं।**

आपने अपनी जिंदगी में कई किलों का दौरा किया होगा, लेकिन राजस्थान के एक खास किले में जाने की गलती मत करना। वहां शाम होते ही कुछ अनजान शक्तियों का साया छा जाता है, जिससे लोग भी वहां जाने से डरते हैं। जहां कभी बस्तियां आबाद थीं, वो अब वीरान हैं, और हर वीराना अपने भीतर ऐसे गहरे रहस्य समेटे हुए है, जो खुलते ही तूफान सा मच जाता है। आज हम ऐसे ही एक वीराने का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जो सदियों से एक अनसुलझी पहली बना हुआ है। राजस्थान के अलवर जिले के अजबगढ़ गांव में ऐसी शापित हवेलियां हैं जो एक ही दिन में वीरान हो गई थीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था यहां? क्यों इन हवेलियों के खंडहरों में कदम रखने की मनाही है? क्या यहां ऐसी शक्तियां हैं जिन पर विज्ञान भरोसा नहीं करता?

### रहस्यमयी साये दिखने का दावा

इस शापित गांव से तंत्र-मंत्र और जादू-टोने की कौन सी कहानियां जुड़ी हैं, कि सैकड़ों साल पहले आबाद रहा ये गांव अब वीरान है और लोग यहां की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते? क्यों इन खंडहरों के दरवाजों पर लिखा है कि यहां भूत रहते हैं? क्यों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहां रहस्यमयी साये देखे हैं?

### तांत्रिक का श्राप

कहते हैं कि इस गांव के एक मकान में कभी लोग रहते थे, और यहां खुशहाली थी। लेकिन एक तांत्रिक के श्राप ने पूरे गांव को वीरान कर दिया। इस गांव के लोग तंत्र-मंत्र और जादू-टोने के माहिर थे, और तांत्रिक आत्माओं को वश में कर उनके जरिए अपने दुश्मनों पर हमला करते थे। लेकिन उनके आपसी झगड़ों और श्राप के कारण गांव पूरी तरह खाली हो गया। अब यहां

खंडहर हो चुके तीन मंजिला मकान की दीवारों पर झाड़ियां उग आई हैं। कुछ दरवाजे टूट चुके हैं और बाकी बचे हैं। पर उन दरवाजों के पीछे छिपे रहस्य सैकड़ों साल पुराने हैं।

### खंडहरों में कदम रखने से मना

इस इलाके के हर बाशिंदे ने हमें चेतावनी दी कि भूलकर भी इन खंडहरों में कदम मत रखना। कुछ ने रात में प्रेत लीला की कहानियां सुनाई, तो कुछ ने दिन में भी यहां जाने से मना किया। लेकिन हमारी जिज्ञासा हमें रोक नहीं पाई, और दिन के समय हम खंडहरों के अंदर गए। अंदर जाते ही हमें समझ आ गया कि लोगों ने यहां आने से क्यों मना किया था। ऐसा लग रहा था जैसे इन खंडहरों के भीतर कोई हमें देख रहा हो। बाहर से आती सूरज की रोशनी भी इन शापित घरों के भीतर एक अजीब सी खौफनाक अनुभूति दे रही थी, जैसे हमें आगाह कर रही हो कि सूरज डूबने से पहले यहां से निकल जाओ।

### रात का अनुभव

हमने गांव के कुछ निवासियों से बात की और महसूस किया कि यह रहस्य और भी गहरा है। कोई भी व्यक्ति रात में खंडहरों के अंदर जाने को तैयार नहीं था, सिवाय एक के। हमने रात के अंधेरे में इन शापित घरों की तरफ बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे-जैसे हम अंधेरे की ओर बढ़े, हम एक कमरे में पहुंचे जहां से अचानक धुआं उठने लगा। क्या ये किसी अज्ञात शक्ति का संकेत था?

### संकेतों का रहस्य

स्थानीय निवासियों ने बताया कि ये अज्ञात शक्तियों का आखिरी संकेत था। हमें सलाह दी गई कि यहां ज्यादा देर तक रुकना खतरनाक हो सकता है।

# मेरा पन्ना



## मुझको भी तो जीने दो



कवयित्री प्रज्ञा श्रीवास्तव प्रज्ञाञ्जलि

जीवन है कितना सुंदर  
मुझको भी तो जीने दो  
माँ की कोख, मुझे भी प्यारी  
दुलार पिता का पाने दो  
में भी तो हूँ अंश तुम्हारा  
फिर भैया ही क्यों लगता प्यारा  
बेटी हूँ तो, क्या मुझको

अधिकार नहीं है जीने का  
बेटे बेटी का भेद अभी भी  
बहुत अधिक है गहराया  
भेद मिटा दो ऐसे तुम  
अधिकार मुझे दो जीने का  
अधिकार मुझे दो जीने का।



विभिन्न विषयों पर आधारित हिन्दी मासिक पत्रिका

# तीर निशाने पर विशिखा

पत्रिका पाने के लिए सम्पर्क करें

सदस्यता  
शुल्क

मूल्य प्रति कापी मात्र 25/- रुपये

एक वर्ष के लिये मात्र 275/- रुपये

दो वर्ष के लिये मात्र 550/- रुपये



**paytm** 9587455444

**BANK DETAILS-**

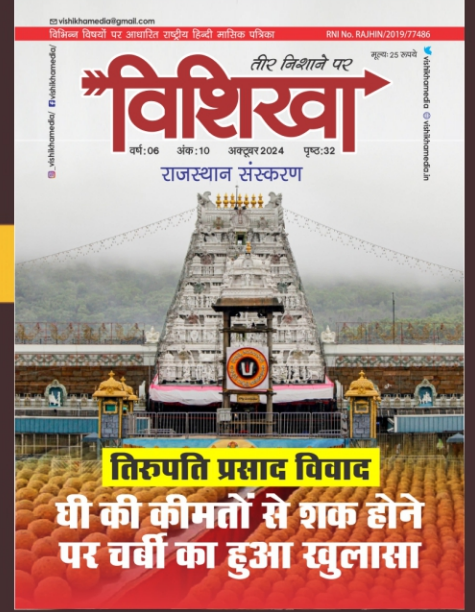
A/C No. - 6345002100000139

IFSC Code- PUNB0634500

A/C Off- VISHIKHA MEDIA

Bank - Punjab National Bank

Branch - NRI Circle, JAIPUR



## विशिखा में विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

| पृष्ठ श्रेणी            | कलर    | अमाउंट     |
|-------------------------|--------|------------|
| बैक फुल पेज             | फोरकलर | ₹ 50,000/- |
| फ्रंट व बैक इनर फुल पेज | फोरकलर | ₹ 30,000/- |
| अन्य फुल पेज            | फोरकलर | ₹ 20,000/- |



मुख्यालय : विशिखा मीडिया 191/56, सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर  
जयपुर-302033 (राज.)

Contactus:+911413562171, 9587455444

E-mail:vishikhamedia@gmail.com | Website:www.vishikhamedia.in

[f vishikhamedia/](#) [@\\_vishikhamedia/](#) [vishikhamedia](#)